Coal for Private Power Plants in Nagpur

*73. SHRI G. PRATHAPA REDDY :
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether the Western Coalfields Ltd. or Coal India Ltd. will supply adequate coal to a private Power Plant if it is set up in Nagpur;

(b) what is the exact policy for supplying coal to Private power plants; and

(c) what are the private power plants in Maharashtra for which Government have received application for the supply of coal ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) and (b) According to the policy of the Government long-term coal linkages are given to thermal power plants on the basis of recommendations of Ministry of Power/Central Electricity Authority. This is uniformly applicable to public sector as well as private sector. The question of coal supply to new private power plant in Nagpur can only be examined on the basis of a specific proposal as and when received.

(c) Long-term coal linkages to the following private sector thermal plants proposed to be located in Maharashtra have been indicated:—

(1) Dahanu TPS 2x250 MW

(2) Bhadravati TPS 1000 MW

(3) Wani-Warora TPS 500 MW

In case of Bhadravati TPS interim linkage has been indicated for a period of two years and for the purpose of long-term supply of coal captive coal mines will be developed by the power company.

न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति

*74. **श्री राम जेठमलानी :,**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार समितियों का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी समितियों का गठन किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछक वर्षों में इन समितियों ने न्यूनतम मजूरी और वेतन के संबंध में अनेक सुझाव दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन सुझावों पर क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) भारतीय श्रम सम्मेलन, 1985 की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 1987 में छः क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित की थी। समितियों की रचना नीचे दर्शायी गयी हैं :

क्षेत्र	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1. पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
2. उत्तर पूर्व क्षेत्र	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
3 दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्ष्यद्वीप
4. उत्तरी क्षेत्र	पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़